

MP-IDSA

Issue Brief

इंडोनेशिया में प्रबोवो सुबियांतो: विदेश नीति और संभावनाएं

ओमप्रकाश दास

मई 16, 2024

सारांश

वैश्विक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं, बढ़ती क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं के बीच प्रबोवो सुबियांतो का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद पर चुना जाना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जोको विडोडो "जोकोवी" के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, प्रबोवो ने एक ऐसी 'रक्षा कूटनीति' को बढ़ावा दिया जिसमें वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने की मंशा दिखाई दी। हालाँकि प्रबोवो ऐसे संकेत भी देते रहे हैं, जो देश के लिए एक मज़बूत रक्षा प्रणाली के साथ मुखर विदेश नीति की हिमायत करता है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया के बढ़ते बहुआयामी सम्बंधों के बीच उम्मीदें और बढ़ती दिखाई देती हैं, इसका एक बड़ा कारण है भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भूमिका और एक रक्षा उत्पाद निर्यातक, तकनीकी एवं डिजिटल शक्ति के तौर पर बढ़ती साख।

परिचय

इंडोनेशिया में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विपक्ष के आरोपों का भी जवाब शीर्ष संवैधानिक अदालत ने दे दिया है। इसी के साथ प्रबोवो सुबियांतो के अगले राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो चुका है। दुनिया के इस तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों पर पूरी दुनिया की नज़रें थीं क्योंकि इंडोनेशिया एक लंबे समय तक भू-राजनीति का अहम खिलाड़ी बना हुआ है। वह न सिर्फ आसियान समूह का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी विश्व-राजनीति और व्यापार के केंद्र में है। दक्षिण-पूर्व एशिया के इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव काफी ज्यादा रहा है, जिसे समय-समय पर अमेरिका चुनौती देता रहा है।

वर्ष 1948 में, इंडोनेशिया के पहले उप-राष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा ने "स्वतंत्र और सक्रिय" विदेश नीति पर जोर दिया था, जो मोटे तौर पर गुटनिरपेक्ष की सोच पर आधारित थी। वर्ष 2014 के अपने पहले कार्यकाल से ही राष्ट्रपति जोको विडोडो 'जोकोवी' ने इसी नीति को सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।¹ वर्ष 2022 में 'जोकोवी' ने रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश की और यही नहीं, उन्होंने दोनों देशों का दौरा किया और यूक्रेन को बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन (2022) में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया।² क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो वर्ष 2023 में इंडोनेशिया जब आसियान की अध्यक्षता कर रहा था, तब भी आसियान ऐसे संकेत देता रहा जो अमेरिका और चीन के बीच तटस्थ संबंध बनाए रखने की हिमायत करता है।^{3,4} ऐसे में पूरी दुनिया की नज़रें प्रबोवो सुबियांतो पर हैं, विशेषकर उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विदेश नीति के संदर्भ में। कुछ प्रेक्षक आश्चर्यचकित दिखते हैं क्योंकि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि प्रबोवो, 'जोकोवी' की नीतियों को ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हालाँकि कुछ अन्य लोगों का यह भी मानना है कि प्रबोवो मौजूदा नीतियों पर अपना प्रभाव डालेंगे।

प्रबोवो सुबियांतो: संक्षिप्त परिचय

प्रबोवो सुबियांतो अगले अक्टूबर में मौजूदा राष्ट्रपति जोको विडोडो 'जोकोवी' की जगह लेंगे। दस सालों से इंडोनेशिया की सत्ता संभाले 'जोकोवी' का यह दूसरा और अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति को दो से ज्यादा कार्यकाल की अनुमति नहीं देता है।⁵

¹ Hangga Fathana, “How Will Indonesia’s Presidential Election Reshape Its Foreign Policy?”, *The Conversation*, 2 February 2024.

² Sebastian Strangio, “Indonesia’s President Jokowi to Visit Russia, Ukraine: Report”, *The Diplomat*, 21 June 2022.

³ Christopher S. Chivvis, Elina Noor and Beatrix Geaghan Breiner, “Indonesia in the Emerging World Order”, Carnegie Endowment for International Peace, 9 November 2023.

⁴ James Scott, “ASEAN’s Strategy for Balancing China’s Belt and Road Initiative and the US Indo-Pacific Strategy”, ASEAN Institute, 9 May 2023.

⁵ “Indonesian Constitution (1945, Consolidated)”, Asian Human Rights Commission, 2021.

इंडोनेशिया के स्पेशल फोर्स के पूर्व जनरल और कमांडर प्रबोवो सुबियांतो को पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो के दामाद के रूप में भी जाना जाता है। सुहार्तो 1998 तक इंडोनेशिया के सैनिक शासक और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1967 से 1998 तक रहा और जिनकी मृत्यु 2008 में हो गई थी। प्रबोवो का सैन्य करियर 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के अंत तक चला, इस दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर सेवाएं दीं।⁶ उनकी अंतिम नियुक्ति 1998 में कोस्ट्राड (इंडोनेशियाई सेना का रणनीतिक रिजर्व कमांड) के कमांडर के रूप में हुई थी।⁷ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के बाद उन्हें सेना छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वह अपने भाई के व्यवसाय में शामिल हो गए। इसके बाद तो प्रबोवो जल्दी ही देश के अग्रणी कारोबारी दिग्गजों में से एक के रूप में स्थापित हो गए।⁸ राजनीति में प्रवेश करने से पहले, प्रबोवो ने ‘नुसंतारा कारोबारी समूह’ को बखूबी आगे बढ़ाया, और तेल - गैस, कोयला खनन, पाम ऑयल और मछली पालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई कंपनियों का प्रबंधन किया।⁹

प्रबोवो ने 2008 में अपने राजनीतिक दल ‘गेरिन्द्र पार्टी’ की स्थापना की¹⁰ और 2009 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मेगावती सुकर्णोपुत्री के साथ उनके उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। लेकिन यह चुनाव, सुकर्णोपुत्री और प्रबोवो, राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार युधोयोनो से हार गए।¹¹ इसके बाद, प्रबोवो ने 2014 और 2019 के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी किस्मत फिर आजमाई, लेकिन दोनों ही मौकों पर वह ‘जोको विडोडो’ ‘जोकोवी’ के हाथों चुनाव हार गए।¹² लेकिन वर्ष 2019 की जीत के बाद ‘जोकोवी’ ने प्रबोवो को अपने मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।¹³

कूटनीति : ‘जोकोवी’ की विरासत

यह काफी हद तक स्पष्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में इंडोनेशिया एक तरफ तो अमेरिका के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए उसे ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक पहुँचाया है, तो वहीं चीन से साथ भी आर्थिक संबंध काफी गहरे हुए हैं।¹⁴ हालांकि, दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवादी

⁶ Salim Said, “**Suharto’s Armed Forces: Building a Power Base in New Order Indonesia, 1966-1998**”, *Asian Survey*, Vol. 38, No. 6, 1998, pp. 535-552.

⁷ Damien Kingsbury, “**The Reform of the Indonesian Armed Forces**”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 22, No. 2, 2000, pp. 302-321.

⁸ Philip Heijmans, “**Wealthy Indonesians Set to Win No Matter Who Becomes President**”, *Bloomberg*, 10 February 2024.

⁹ Kiki Siregar, “**Prabowo’s Set to Become President, so Why Are Foreign Investors Still Wary of Indonesia’s New Capital Nusantara?**”, *Channel News Asia*, 1 April 2024.

¹⁰ Edward Aspinall, “**Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy**”, *Indonesia, Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, No. 99, 2015, pp. 1-28.

¹¹ Nadia Bulkin, “**Indonesia’s Political Personalities**”, *Carnegie Endowment for International Peace*, 24 October 2013.

¹² Natalie Sambhi, “**Indonesia’s Eras: Reflections on Jokowi’s Legacy and Prabowo’s Presidency**”, *Brookings*, 28 February 2024.

¹³ Ibid.

¹⁴ “**FACT SHEET: President Joseph R. Biden and President Joko Widodo Announce the U.S.-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership**”, *The White House*, 13 November 2023.

दावों ने एक लंबे समय से तनाव की स्थिति पैदा कर रखी है।¹⁵ इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में इंडोनेशिया अपनी लंबे समय से चली आ रही ‘स्वतंत्र और सक्रिय’ विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करने का दावा भी करता रहा है।¹⁶ ‘जोकोवी’ प्रशासन ने एक तरफ तो क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है, तो वहीं बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए चीनी निवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। ‘जोकोवी’ ने पिछले दस सालों में ‘आर्थिक कूटनीति’ का सहारा लेते हुए देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जिससे इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली है। विदेशी निवेश ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज़ किया है। इन परियोजनाओं में ‘नुसंतरा’ में नई राजधानी का निर्माण, चीन समर्थित जकार्ता-बांडुंग हाई-स्पीड रेलवे परियोजना शामिल है, जिसे अभी और विस्तार देने की बात हो रही है। हालांकि, इस सब के बीच, इंडोनेशिया पर चीनी कर्ज के बोझ का जंजाल बड़े सवाल खड़े कर रहा है।¹⁷

विदेश नीति : प्रबोवो और संभावनाएं !

प्रबोवो सुबियांतो ऐसे समय में राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे हैं जब एक तरफ ‘पश्चिम पापुआ’ में संघर्ष जारी है,¹⁸ तो दूसरी ओर क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे लगातार कायम हैं। पिछले सालों में इंडोनेशिया की विदेश नीति में एक खास तरह की निरंतरता देखने को मिली है। पिछले पांच सालों में प्रबोवो इस सरकार में बतौर रक्षा मंत्री सेवाएं देते रहे हैं और इस दौरान कई भू-राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने न सिर्फ अपनी राय रखी है, बल्कि दखल भी दिया है।

अप्रैल 2024 के शुरुआती दिनों में ही इंडोनेशिया के निर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने चीन, जापान और मलेशिया की आधिकारिक यात्रा की।¹⁹ उल्लेखनीय है कि उनकी पहली यात्रा बीजिंग की थी। चुनाव के दौरान, प्रबोवो ने खुद को एक ऐसे संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किया था जो बिना किसी बड़े उतार-चढ़ाव के मौजूदा विदेश नीति के ढांचे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को संतुलित करने के लिए निरंतरता बनाए रखने और ‘जोकोवी’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का भी भरोसा दिया।²⁰ अपने लगभग दस साल के कार्यकाल के दौरान, ‘जोकोवी’ ने कम से कम छह

¹⁵ Damos Dumoli Agusman, “**Natuna Waters: Explaining a Flashpoint between Indonesia and China**”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 20, No. 4, August 2023, pp. 531–562.

¹⁶ Dewi Fortuna Anwar, “**Indonesia’s Path Between the Reefs**”, *Foreign Affairs*, 27 February 2024.

¹⁷ Daniel Peterson, “**China’s Power Play in Indonesia: Infrastructure Investment and Territorial Incursions**”, *Open Edition Journals*, 27 June 2023.

¹⁸ पश्चिम पापुआ संघर्ष में इंडोनेशिया और फ्री पापुआ मूवमेंट (ओपीएम) नामक संगठन शामिल हैं, जो 50 से अधिक वर्षों से चल रहा एक अलगाववादी संघर्ष है। यह संघर्ष, 1961 में एक विवादित जनमत संग्रह और इंडोनेशियाई के पापुआ के इस क्षेत्र पर कब्जे की कोशिशों के बाद से उपजा है। ओपीएम गुरिल्ला युद्ध के ज़रिए सैन्य, पुलिस और नागरिकों को निशाना बनाता रहता है।

¹⁹ Leo Suryadinata and Siwage Dharma Negara, “**Analysing Prabowo Subianto’s Visits to China, Japan, and Malaysia**”, *FULCRUM*, 16 April 2024.

²⁰ Prashanth Parameswaran, “**Next Leader Will Likely Seek Continuity in Indonesia’s Foreign Policy**”, *GIS*, 3 January 2024.

बार चीन का दौरा किया है, जो राष्ट्रपति शी और 'जोकोवी' के बीच के तालमेल को भी दिखाता है।²¹ हालांकि, राष्ट्रपति 'जोकोवी' की इस बात के लिए आलोचना होती रही है कि वह इंडोनेशियाई जलक्षेत्र में चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को लेकर नरम रुख अपनाते रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि नौकाएं अक्सर बड़े चीनी तटरक्षक जहाजों की सुरक्षा में होती हैं।^{22,23,24}

प्रबोवो के चुनावी घोषणा-पत्र में 8 व्यापक दृष्टिकोण और 17 प्राथमिकता वाली नीतियों को शामिल किया गया है।²⁵ यह घोषणा-पत्र कहता है कि “एक मजबूत देश ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकता है।”²⁶ 'जोकोवी' की विदेश नीति से अलग, यह सोच वैदेशिक संबंधों और नीतियों में अधिक मुखर रुख की ओर संकेत करती है। घोषणा-पत्र स्पष्ट रूप से, देश के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर देता है।²⁷ वर्ष 2024 के चुनाव के लिए प्रबोवो के चुनावी घोषणा-पत्र की नीतिगत प्राथमिकताओं में, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन और फिलिस्तीन में जारी संघर्ष, दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ संभावित सशस्त्र संघर्ष की आशंका, वैश्विक आर्थिक मंदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को शामिल किया गया है।^{28,29} इन वैश्विक मुद्दों को प्राथमिकताओं की इस सूची में शामिल करना यह बताता है कि प्रबोवो उन खतरों को लेकर जागरूक हैं जो इंडोनेशिया से सीधा वास्ता रखते हैं और वह मुद्दे भी जो घटित तो सुदूर पश्चिम में हो रहे हैं लेकिन वह वैश्विक शक्तियों के संघर्ष से ही उपजे हैं।

तात्कालिक इतिहास पर नजर डालें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें प्रबोवो ने उन कोशिशों को अपना समर्थन दिया है जो किसी भी राष्ट्र की अपनी आत्मरक्षा की तैयारी के लिए ज़रूरी हैं।³⁰ उन्होंने इसे हथियारों की होड़ से अलग हट कर देखने की कोशिश की है जिसमें परमाणु रक्षा उपकरण तक शामिल हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया द्वारा परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की कोशिश करना। हालांकि 2021 में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में प्रबोवो ने 'परमाणु मुक्त दक्षिण पूर्व एशिया' के सिद्धांत का समर्थन किया था।³¹ जून 2023 में सिंगापुर में हुए 'शांगरी-ला डायलॉग' सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष

²¹ Warief Djajanto Basorie, “**Prabowo in China: Indonesia’s President-Elect on the World Stage**”, Lowy Institute, 10 April 2024.

²² Ralph Jennings, “**Indonesia Sounds a Soft Warning in Renaming Part of Disputed Sea**”, Voice of America, 19 July 2017.

²³ Joe Cochrane, “**China’s Coast Guard Rams Fishing Boat to Free It From Indonesian Authorities**”, *The New York Times*, 22 March 2016.

²⁴ Warief Djajanto Basorie, “**Prabowo in China: Indonesia’s President-Elect on the World Stage**”, no. 21.

²⁵ Noto Suoneto, “**Where Does Indonesia’s Prabowo Subianto Stand on Foreign Policy?**”, *The Diplomat*, 30 November 2023.

²⁶ “**Vision, Mission and Programs**”, Prabowo Gibran 2024.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Noto Suoneto, “**Where Does Indonesia’s Prabowo Subianto Stand on Foreign Policy?**”, *The Diplomat*, 30 November 2023.

³⁰ Kate Lamb, “**Indonesia's Defence Minister Says 'Understands, Respects' AUKUS Pact**”, *Reuters*, 22 November 2021.

³¹ Chris Barrett, “**Indonesia Was Up in Arms over AUKUS but Its Defence Minister Has Different Take**”, *The Sydney Morning Herald*, 22 November 2021.

के समाधान के लिए प्रबोवो ने एक व्यापक शांति योजना का प्रस्ताव किया था।³² उनकी यह पहल स्पष्ट करती है कि कैसे प्रबोवो अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में इंडोनेशिया की भी भूमिका देखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबोवो के नेतृत्व में इंडोनेशिया ने फिलिस्तीनी संप्रभुता की वकालत करते हुए गजा से संबंधित मुद्दों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की पहल की है। इजराइल के गजा के कई हिस्सों पर कब्जे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में इंडोनेशिया का अनुरोध³³ फिलिस्तीनियों के लिए उनके सक्रिय समर्थन को दर्शाता है। फिलिस्तीन समर्थक यह दृष्टिकोण निर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो के कार्यकाल के दौरान जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है जिसमें इजराइल से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बहिष्कार की कार्रवाई भी शामिल है।³⁴

2023 में आसियान का अध्यक्ष होने के नाते इंडोनेशिया की म्यांमार में सैन्य शासन और हिंसा को रोकने को लेकर भारी दबाव था लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया। प्रबोवो की पृष्ठभूमि सेना में एक वरिष्ठ जनरल की रही है। नवंबर 2023 में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में प्रबोवो ने आसियान के अपने समकक्षों से “म्यांमार में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ठोस प्रगति पर जोर देने का आग्रह किया था जो फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के तुरंत बाद से गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच गया है।”³⁵ ऐसे में अब यह उम्मीद और ज्यादा प्रबल हो गई है कि प्रबोवो एक नई सोच के साथ म्यांमार के सैन्य शासकों के साथ गृहयुद्ध में बीच-बचाव की कोशिशों पर पहल करेंगे।³⁶ यह खासकर एक ऐसे समय में होने जा रहा है जब म्यांमार में जुंटा और लोकतंत्र समर्थक हथियारबंद समूहों के बीच भारी संघर्ष जारी है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से इंडोनेशिया म्यांमार के सैन्य शासकों के बजाय लोकतंत्र समर्थक ताकतों के पक्ष में भी बोलता दिखा है।³⁷

रक्षा मंत्री के रूप में प्रबोवो ने कुछ ऐसी चुनौतियों के समाधान की ओर कदम बढ़ाए हैं जो उन्हें विरासत में मिली थी जिसमें देश के रक्षा उद्योग के पुनर्निर्माण के लिए कई व्यापक कदम भी शामिल रहे हैं।³⁸ इसके अलावा चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, जापान और अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है।³⁹ प्रबोवो ने ‘रक्षा कूटनीति’ पर जोर देते हुए इंडोनेशिया के गुटनिरपेक्ष रुख के साथ तालमेल बिठाया है।⁴⁰ रक्षा खरीद के मामले में कई तरह के प्रतिबंधों से बचने के लिए ‘जोकोवी’ और प्रबोवो ने पश्चिमी देशों और उनके विरोधियों के बीच एक खास तरह का संतुलन बनाया है। इस संतुलन का

³² Audina Nur, “**Controversy Surrounds Defense Minister Prabowo’s Peace Plan for the Russia-Ukraine Conflict**”, *Indonesia Business Post*, 13 June 2023.

³³ Resty Woro Yuniar, “**Prabowo Set to Keep Indonesia’s Strong Pro-Palestinian Stance amid ICJ Case**”, *South China Morning Post*, 27 February 2024.

³⁴ Ibid.

³⁵ Sebastian Strangio, “**ASEAN Defense Ministers Call For Gaza Ceasefire, Myanmar Solution**”, *The Diplomat*, 16 November 2023.

³⁶ Brian Harding, “**How Might Prabowo Navigate Conflict, Competition as Indonesia’s President?**”, United States Institute of Peace, 22 February 2024.

³⁷ Ibid.

³⁸ Omar R. Joenoes, “**Prospects for Indonesian Diplomatic Style Under a New President in the Post-Jokowi Era**”, Central European Institute of Asian Studies, 10 February 2024.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Noto Suoneto and Ananta Evander, “**Assessing Prabowo Subianto’s Defense Diplomacy**”, *The Diplomat*, 18 June 2021.

एक उदाहरण है वर्ष 2021 में रूस से ‘सुखोई’ लड़ाकू जहाजों की खरीद से पीछे हटना⁴¹ और उसके विकल्प के तौर पर प्रबोवो ने एक यूरोपीय देश फ्रांस में निर्मित जेट ‘राफल’ को चुनना।⁴² वहीं जून 2023 में प्रबोवो और उनके जर्मन समकक्ष ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।⁴³ यह कहा जा सकता है कि प्रबोवो ने ‘रक्षा कूटनीति’ की अवधारणा को अलग-अलग विविध साझेदारों के साथ जोड़ा है।

भारत-इंडोनेशियाई संबंध, प्रबोवो और संभावनाएं

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणामों की ‘आधिकारिक घोषणा’ से पहले ही (फरवरी में) इंडोनेशिया के निर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को बधाई दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने “भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी” के बढ़ने की आशा व्यक्त की।⁴⁴ प्रबोवो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया में बधाई संदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और “इंडोनेशिया और भारत के बीच ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ को और अधिक मजबूत करने की भावना” व्यक्त की।⁴⁵

बधाईयों और शुभकामनाओं का यह आदान-प्रदान राजनयिक-कूटनीतिक शिष्टाचार से आगे इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि विस्तारवादी चीन की आशंकाओं की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सहयोग स्थापित करने को लेकर भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच हुए ‘रक्षा सहयोग समझौता’ इस भागीदारी को आगे बढ़ाने की मंशा को स्पष्ट करता है जिसका उद्देश्य ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ की दिशा में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।⁴⁶

चुनाव अभियान के दौरान प्रबोवो के बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं।^{47,48} व्यापक नज़रिए से देखें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों से गहरा रिश्ता रहा है जो 1951 से सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राजनयिक संबंधों द्वारा और अधिक पुख्ता हुआ है।⁴⁹ दोनों देशों का एक साझा इतिहास है जिसमें लोगों के बीच आपसी संबंध, उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष

⁴¹ Joe Saballa, “Indonesia Backs Out of Sukhoi Deal for US, French Warplanes”, *The Defense Post*, 23 December 2021.

⁴² Ibid.

⁴³ Omar R. Joenoes, “Prospects for Indonesian Diplomatic Style Under a New President in the Post-Jokowi Era”, Central European Institute of Asian Studies, 10 February 2024.

⁴⁴ Narendra Modi (@narendramodi), “Congratulations to the people of Indonesia on the successful Presidential elections and @prabowo on the lead”, X (formerly Twitter), 18 February 2024, 8:18 PM.

⁴⁵ Prabowo Subianto (@prabowo), “Thank you, Prime Minister @narendramodi, for your congratulatory message on our elections”, X (formerly Twitter), 19 February 2024, 4:50 PM.

⁴⁶ “Defence Relations”, Consulate General of India, Indonesia.

⁴⁷ Hangga Fathana, “How Will Indonesia’s Presidential Election Reshape Its Foreign Policy?”, no. 1.

⁴⁸ CSIS Indonesia, “Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri”, YouTube, 13 November 2023.

⁴⁹ “Treaty of Friendship between India and the Republic of Indonesia [1951]”, *Indian Treaty Series*, 3 March 1951.

का साझा दर्शन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक-दूसरे की स्वतंत्रता के लिए मुखर समर्थन भी शामिल है। दोनों देश लोकतांत्रिक सिद्धांतों, बहुलवादी संस्कृति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिमायती रहे हैं। वहीं, भारत ने इंडोनेशिया को दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख सहयोगी मानते हुए अपने रिश्तों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक पहुंचाया है।⁵⁰ इस प्रक्रिया में वर्ष 2018 के ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ ने अहम भूमिका निभाई है।⁵¹ पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विशेष रूप से रक्षा उद्योग संबंधों, अनुसंधान और संयुक्त उत्पादन में सहयोग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों को लगातार समृद्ध किया है।^{52, 53}

चुनाव के पहले ही कई मंचों से प्रबोवो ने ‘आर्थिक कूटनीति’ को लेकर अपने विचार रखे थे जिसमें “एकोनोमी पंचसिला”^{54, 55} के विचार को अपनाने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। उनकी यह सोच बताती है कि कैसे पूंजीवाद और समाजवाद के तत्वों को एक साथ लाया जाए जिसके जरिए इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था किसी पर निर्भर रहने के बजाए स्वायत्त हो।⁵⁶

इस लेख के पहले हिस्से में हम देख चुके हैं कि कैसे प्रबोवो ने लगातार देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की वकालत की है, खासकर आत्मरक्षा के मोर्चे पर। इसके लिए रक्षा साजो-सामान और उपकरणों के प्लेटफार्मों में विविधता लाना और आधुनिकीकरण पर ज़ोर दिया गया है।⁵⁷ ऐसे में भारत की भूमिका बेहद खास हो जाती है क्योंकि वर्तमान समय में भारत एक रक्षा विनिर्माण केंद्र और निर्यातक के रूप में उभर रहा है।⁵⁸ पारंपरिक रक्षा आपूर्तिकर्ताओं से अलग हट कर भारत एक भरोसेमंद और व्यावहारिक विकल्प के रूप में अपने को स्थापित कर रहा है।⁵⁹ गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रबोवो ने भारत से सैन्य उपकरणों के अधिग्रहण

⁵⁰ “**India - Indonesia Bilateral Relations: Brief Note**”, Embassy of India, Jakarta, August 2023.

⁵¹ “**7th India-Indonesia Joint Defence Cooperation Committee Meeting Held in New Delhi**”, Press Information Bureau, Ministry of Defence, Government of India, 3 May 2024.

⁵² Ibid.

⁵³ “**Defence Secretary & Secretary General of MoD, Indonesia to Co-Chair 7th Joint Defence Cooperation Committee Meeting in New Delhi**”, Press Information Bureau, Ministry of Defence, Government of India, 2 May 2024.

⁵⁴ एकोनोमी पंचसिला, जिसे “इंडोनेशियाई लोकलुभावन अर्थशास्त्र” के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य पंचशिल के पांच सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना है। “पंचसिला अर्थव्यवस्था” शब्द का प्रयोग पहली बार 1967 में एमिल सलीम द्वारा किया गया था। पंचशिला अर्थव्यवस्था का मूल आर्थिक दर्शन और पंचशिला दर्शन से बना है। अर्थव्यवस्था मानव जीवन की आवश्यकताओं की व्याख्या करती है, जबकि पंचशील मनुष्य के ईश्वरीय तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।

⁵⁵ Palupi Lindiasari, “**The Pancasila Economic System as a Foundation for Indonesia's Economic Resilience from a Philosophy of Science Perspective**”, *Journal of National Resilience Strategic Studies*, 21 May 2023.

⁵⁶ “**Indonesia's Prabowo Subianto Eyes Indian Alliance and Arms Deals**”, Indian Defence Research Wing, 19 February 2024.

⁵⁷ Ian Storey, “**Indonesia's Defence Procurement Strategy: Diversification but at What Cost?**”, FULCRUM, 20 April 2023.

⁵⁸ Abhishek Kumar, “**India: An Emerging Defence Manufacturing Hub**”, Economic Diplomacy Division, 9 January 2024.

⁵⁹ “**Indonesia's Prabowo Subianto Eyes Indian Alliance and Arms Deals**”, no. 56.

में समय-समय पर अपनी रुचि भी जताई है⁶⁰ जो प्रबोवो के इंडोनेशियाई सेना के आधुनिकीकरण के उनके घोषित उद्देश्य से मेल खाती है।⁶¹

इंडोनेशिया और भारत के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग, विशेष रूप से उनके संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के रूप में पूरी दुनिया के सामने है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडोनेशिया अपने समुद्री क्षेत्र के 'नातुना सागर' में चीनी तट रक्षकों की उपस्थिति की चुनौतियों से लगातार जूझ रहा है।⁶² दोनों देशों के बीच होने वाले साझा सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां इस भागीदारी के और व्यापक होने की ओर इशारा करते हैं जो इंडोनेशिया की व्यापक तटरेखा की सुरक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।

निष्कर्ष

इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के लिए प्रबोवो सुबियांतो का निर्वाचन एक जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हुआ है। इन जटिल सवालों में कई क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताएं भी शामिल हैं। इंडोनेशिया की विदेश नीति में निरंतरता की प्रवृत्ति के बावजूद, प्रबोवो के कार्यकाल में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक मुखरता की स्पष्ट संभावनाएं हैं। उनके चुनावी घोषणा-पत्र की प्राथमिकताएं और पिछले बयान, इंडोनेशिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, क्षेत्रीय संघर्षों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने की ओर भी संकेत करते हैं। रक्षा साझेदारी में विविधता और वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन की कोशिश आगे बढ़ती लगती हैं। इस सबके बीच यह कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया की विदेश नीति में क्षेत्रीय चुनौतियों के मद्देनजर मुखर सुरक्षा नीति के साथ-साथ आर्थिक और रक्षा कूटनीति के तत्वों की बड़ी भूमिका हो सकती है। हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया ने विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय मामलों में सहयोग की प्रक्रिया को तेज़ किया है। संभावनाएं इस बात को लेकर भी हैं कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग का नया चरण शुरू हो सकता है। हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र की कूटनीतिक चुनौतियों को लेकर दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण बेहद महत्वपूर्ण होगा, जो दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और नियम आधारित व्यवस्था को उसके सही अर्थों में लागू करने के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

⁶⁰ Dipanjan Roy Chaudhury, “Indonesia’s President-elect Prabowo Subianto Keen on BrahMos Purchase; Emulating India’s Mid-day Meal Scheme for Schools”, *The Economic Times*, 18 February 2024.

⁶¹ Hadza Min Fadhli Robby, “Subianto Govt Can Help India-Indonesia Ties in 4 Ways. But Some Anxieties Can't Be Ruled out”, *The Print*, 22 February 2024.

⁶² “India, Indonesia Agree to Enhance Collaboration in Defence Industry, Maritime Security”, *The Hindu*, 3 May 2024.

About the Author



Mr. Om Prakash Das is Research Fellow at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses is a non-partisan, autonomous body dedicated to objective research and policy relevant studies on all aspects of defence and security. Its mission is to promote national and international security through the generation and dissemination of knowledge on defence and security-related issues.

Disclaimer: Views expressed in Manohar Parrikar IDSA's publications and on its website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Manohar Parrikar IDSA or the Government of India.

© Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) 2024